हिन्दी दैनिक

इंडिया वार्ता

R.N.I NO. UTTHIN/2011/39104

सच के साथ-जन के साथ

लोकतंत्र में जनसरोकार का सशक्त माध्यम

आत्मिक वाणी

मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना अपने मन मे मेरी बातों को याद रखना क्योकि ऐसा करने से तेरे जीवन के दिन और तेरे वर्ष और बढ़ेंगे। तेरा अधिकाधिक कल्याण ही होगा मेरे पुत्र करूणा और सच्चाई कभी तुझ से अलग ना हो तू उनको अपने गले का हार बना कर रखना और उनकों अपने हृदय पटल पर लिख लेना तब तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों की दृष्टि में कृपा का पात्र होगा।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड़ के मदरसों में स्कॉलरशिप.. 8

वर्ष : 15 अंक : 01 | देहरादून,शुक्रवार 18 जुलाई 2025 | शुल्क : पचास पैंसे | पृष्ठ संख्या : 08

युवाओं को कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने के लिए विभागीय सचिव समन्वय के साथ करें कार्य

सचिवालय में कौशल विकास और श्रम विभाग की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश

इंडिया वार्ता ब्यूरो

देहरादून । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कौशल विकास और श्रम विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में युवाओं को कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने के लिए सभी संबंधित विभागीय सचिव समन्वय बनाकर कार्य करें। उन्होंने मुख्य सचिव को सचिवों के साथ बैठक कर इसके लिए ठोस रणनीति बनाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कौशल विकास को इन्क्यूबेशन और ग्रोथ सेंटरों से जोड़ने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद में स्थानीय लोगों को प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, मिस्त्री जैसे कार्यों के लिए बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। उद्योगों की मांग और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण कोर्स तैयार किए जाएं। प्रशिक्षण केंद्रों में अत्याधुनिक मशीनें, प्रयोगशालाएं (लैब्स) और स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना की जाए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर जनपद की पारंपरिक पहचान को ध्यान में रखते हुए लोगों को कौशल विकास और प्रशिक्षण से जोड़ा जाए। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण बढ़ाने के साथ ही सभी कुशल श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि बाल श्रम मुक्ति के लिए लक्षित पुनर्वास से संबंधित कार्रवाई हेतु शीघ्र योजना बनायी जाए। राज्य के बड़े जनपदों में बाल श्रम मुक्ति के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि स्वरोजगार के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिये विशेष कौशल विकास केंद्रों की

– शेष पृष्ठ 7 पर ...

सीएम पुष्कर सिंह धामी का सख्त रुख, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ विजिलेंस को दी खुली छूट

2021 में सिर्फ पांच गिरफ्तारी, 2024 में 38 तक पहुंची गिरफ्तारियों की संख्या

इंडिया वार्ता ब्यूरो

देहरादून । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजिलेंस को भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए खुली छूट प्रदान की हुई है। इसका असर, साल दर साल बढ़ते विजिलेंस ट्रैप और गिरफ्तारियों की संख्या में रूप में नजर आ रहा है। यही नहीं मजबूत साक्ष्य के आधार विजिलेंस गत साढ़े चार साल में 71 प्रतिशत मामलों में आरोपियों को कोर्ट से सजा दिलाने में कामयाब रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य का पदभार संभालते ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर रुख साफ कर दिया था। इसका साफ असर विजिलेंस की कार्यवाही में नजर आ रहा है।

बीते चार साल में बडे से बड़े आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य में साल दर साल विजिलेंस ट्रैप और गिरफ्तारियों के साथ ही सजा के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। इस दौरान विजिलेंस ने कुल 82 ट्रैप में 94 गिरफ्तारियों को अंजाम दिया, जिसमें 13 राजपत्रित अधिकारी शामिल हैं। बीते साढ़े चार साल से विजिलेंस के पास कुल 125 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें 18 में सामान्य जांच, 25 में खुली जांच के बाद 82 ट्रैप किए गए। गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस ठोस साक्ष्य और मजबूत पैरवी से कोर्ट में सजा की दर को भी 71 प्रतिशत तक ले जान में कामयाब रही है। इससे साफ है कि सरकार भ्रष्टाचार की समस्या को जड़ से खत्म करने के मिशन पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सतर्कता विभाग ने शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नम्बर 1064 भी जारी किया है। यही नहीं मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को अंतिम फैसला आने तक आरोपियों को पूर्व के-दायित्व या अहम जिम्मेदारी नहीं देने के साथ ही ट्रैप के मामलों में अभियोजन की प्रक्रिया में तेजी जाने के निर्देश दिए हैं।

01-लोनिवि एई नैनीताल जिले में लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता को ठेकेदार से घ्10 हजार रिश्वत मांगने पर रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। 02-यूपीसीएल जेई-देहरादून के हरबर्टपुर सब स्टेशन के एक जेई को विजिलेंस ने घ्15000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। 03-एलआईयू

– शेष पृष्ठ 7 पर ...

मलाईदार अनुभाग पाने को लगाई सिफारिश तो होगी कार्रवाई

देहरादून,इंडिया वार्ता ब्यूरो । सचिवालय प्रशासन ने वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2025 को जारी कर दिया है। अब मलाईदार अनुभाग पाने को सिफारिश लगाने वाले अधिकारी, कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अनुभाग अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी एक अनुभाग में पांच साल से अधिक नहीं रह पाएंगे। सचिव सचिवालय प्रशासन दीपेंद्र कुमार चौधरी की ओर से तबादला नीति जारी की गई। श्रेणी क, ख, ग स्तर के अधिकारी, कर्मचारियों के तबादलों को तीन समितियों का गठन किया गया है। एक अनुभाग में तैनाती को लेकर समय सीमा तय कर दी गई है। सिर्फ प्रशासनिक और अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़ कर तय समय से पहले तबादला नहीं होगा। श्रेणी क अफसरों का विभाग में तैनाती समय तीन वर्ष रहेगा। कम्प्यूटर सहायक का एक अनुभाग में अधिकतम समय सात वर्ष तय किया गया है। श्रेणी क क अफसरों के लिए मुख्य सचिव से अनुमोदन लेना होगा। श्रेणी ख और ग में सचिव सचिवालय प्रशासन का अनुमोदन अनिवार्य होगा। बिना किसी ठोस कारण के कर्मचारी सरेंडर नहीं किए जाएंगे। एक अनुभाग से तबादला होने पर पांच साल से पहले वहीं तैनाती नहीं मिलेगी। संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों, कर्मचारियों की तैनाती महत्वपूर्ण और संवेदनशील विभागों, अनुभागों में नहीं की जाएगी। ज्वाइन न करने वालों को नहीं होगा वेतन का भुगतान विभाग, अनुभाग बदलने के तीन दिन के भीतर ज्वाइन न करने वालों का वेतन जारी नहीं होगा। बिना प्रतिस्थानी का इंतजार किए बिना कार्यमुक्त होना होगा। तबादला होने पर अवकाश मंजूर नहीं होगा। आदेश न मानने पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

युवक पर फायरिंग करने के तीन आरोपी तमंचे सहित गिरफ्तार

इंडिया वार्ता ब्यूरो

देहरादून । युवक पर फायरिंग कर जानलेवा हमले के तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिनके पास से तीन तमंचे व कारतूस बरामद किये गये है। आरोपियों द्वारा पुरानी रंजिश के चलते घटना को अंजाम दिया गया था। जानकारी के अनुसार बीती 12 जुलाई को वैभव रावत पुत्र दिनेश रावत, निवासी शिव विहार कालोनी गुमानीवाला ने थाना ऋषिकेश में तहरीर देकर बताया गया था कि हर्ष चौधरी उर्फ हर्ष जाट, लव कांबोज व अन्य व्यक्तियों द्वारा बैराज रोड ऋषिकेश में वाहन में आकर उन पर तथा उसके साथियों पर अचानक फायर करके जानलेवा हमला किया गया और वह मौके

से भाग निकले। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गयी। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस टीमों द्वारा बीती शाम एक सूचना के आधार पर घटना में शामिल तीन आरोपियों हिंमाशु उर्फ प्रशान्त, दीक्षित कुमार एवं विशाल कश्यप उर्फ सूटर को तीन देशी तमंचो व तीन कारतूसों के साथ खाण्डगांव पार्किंग के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

सम्पादकीय

उत्तराखंड में बना नया कीर्तिमान

हरेला बनता जन आंदोलन....

इस बार राज्य सरकार हरेला को महापर्व के रूप में मान रही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस महोत्सव का आगाज किया है प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस महापूर्व की शुरुआत बड़े स्तर पर की है लोक संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक यह त्यौहार इस बार उत्तराखंड में जोर शोर से मनाया जा रहा है पुष्कर सिंह धामी की थीम हरेला का त्योहार मानो धरती मां का ऋण चूकाओ इस थीम पर आधारित हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जा रहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा यह त्योहार उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ा हुआ है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहां है हरेला का यह त्यौहार हमें प्रकृति के और करीब लेकर जाता है उन्होंने कहा है प्रकृति को सवारने सुरक्षित रखने का हर एक उत्तराखंड में रहने वाले लोगों का अपना दायित्व है उन्होंने कहा है इस बार हरेला पर्व पर 5 लाख पौधे लगाने का कार्य सुनिश्चित था लेकिन मुख्यमंत्री की उम्दा छवि के कारण यह आंकड़ा 7 लाख के करीब पहुंच गया इस संगठन में तमाम तरह के लोगों ने अपना अपना सहयोग प्रकृति को दिया है इस बार के हरेला पर्व पर पहली बार 11300 फीट की ऊंचाई पर भी पौधारोपण किया गया हरेला पर्व पर्व पर वन विभाग ने सबसे ज्यादा ऊंचाई वाले स्थान पर पौधारोपण कर एक अपने आप में मिसाल कायम की है तकरीबन एक एकड़ में जटामांसी के पौधों को रोपा गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है उत्तराखंड की जनता से अपील की है अपने जीवन के विशेष अवसरों पर पौधारोपण जरूर करें और उनकी देखभाल कर यह सुनिश्चित करें की जो पौधा हमने लगाया है वह सुरक्षित है इस बार हरेला पर्व ने तकरीबन आठ लाख के करीब पूरे प्रदेश में पौधारोपण किया गया है माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में राज्य में हर रोज नए-नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं जो जनता के लिए मिल का पत्थर साबित हो रहे हैं आने वाले दिनों में सरकार का प्रयास है सबका साथ सबका विकास और सब का विश्वास थीम पर पार्टी कार्य करेगी ताकि जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाए।

सरकार का निशाना,समोसा जलेबी कचोरी नहीं बल्कि खाद्य पदार्थों में छिपे,अतिरिक्त चीनी व तेल केहानिकारक सेवन के विकल्प से जागरूक कराना है

-एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं

गोंदिया – वैश्विक स्तरपर दुनियाँ के हर देश के विद्वान से लेकर साधारण आम व्यक्ति को यह मानना पड़ेगा कि अर्ध सत्य, झूठ से भी अधिक खतरनाक व हानिकारक होता है इसीलिए किसी भी आदेश/निर्देश/जानकारी या बातचीत क़ा पूरा सत्य, इसका उद्देश्य,पारदर्शिता जानना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। आज हम इस विषय पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं,क्योंकि पिछले तीन दिनों से मैं एडवोकेटकिशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र, सोशल इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया में लगातार आर्टिकल्स, डिबेट विश्लेषण देख सुन व पढ़ रहा हूं कि समोसा जलेबी कचोरी फ्रेंच फ्राइज बहुत नुकसान कारक हैं,उससे बीमारियां होती है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इन खाद्य उत्पादों पर चेतावनी निर्देश जारी करने का निर्देश दिया है इसलिए मैं पिछले दो दिनों से लगातार इसपर रिसर्च कर अपना यह आर्टिकल तैयार किया हूं। असल में यह बात शुरू हुई है पीएम की अपील से हुई, उन्होंने 28 जनवरी 2025 को देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह में फिट इंडिया मूवमेंट की बात करते हुए नागरिकों से अपील की थी कि वे तेल की खपत में 10 पेर्सेंट की कमी करें और स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं। उन्होंने अपने कार्यक्रम %मन की बात% में भी यह संदेश दिया था कि भारत को %स्वस्थ भारत% बनाना है और यह बदलाव आम लोगों की आदतों से ही आएगा। फिर ग्लोबल बर्डन आफ डिजीज (जीबीडी) रिपोर्ट 2025 में भी बताया गया कि भारत में 2021 में 18 करोड़ वयस्क मोटापे के शिकार थे जो यह आंकड़ा 2050 में बढ़कर 44.9 करोड़ तक पहुंच सकता है? हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जून 2025 में सभी स्कूलों/ दफ्तरों/ संस्थानों में खाने-पीने की लोकप्रिय चीजों जैसे पिज़्ज़ा बर्गर समोसा वडा पाव कचोरी इत्यादि में मौजूद तेल में चीनी की मात्रा दिखाने वाले बोर्ड लगाने का प्रस्ताव/ निर्देश दिया था। फिर 14 मई 2025 को शिक्षा मंत्रालय ने सीबीएसई स्कूलों में शुगर बोर्ड लगाने का निर्देश दिया था अब यह उसको विस्तारित कर तेल बोर्ड लगाने का निर्देश 2 दिन पूर्व ही दिया है। यानी कुल मिलाकर यह पूरी कवायत खाद्य पदार्थों में,चीनी तेल की मात्रा को रेखांकित कर उसका विकल्प चुनकर खाने व अपनीं जीवनशैली से जुड़ी तेजी से बढ़ती हुई बीमारियों व मोटापे को नियंत्रण में रखना व निपटने का एक सुझाव मात्र है, नाकि कोई जोर जबरदस्ती है, यदि इस सुझाव को पढ़ने वाला उसे नहीं मानता तो, उसकी मर्जी है। बस! यही इस मुद्दे का सार है। परंतु इसे मीडिया के माध्यम से विवादित बनाया जा रहा है,ऐसा मेरा मानना है। चूँकि भारत में जीवनशैली से जुड़ी तेजी से बढ़ती बीमारियों व मोटापे से निपटने के लिए केंद्र सरकार की नई पहल आई है,इसके निर्देश जारी कर दिए गए हैं, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी क़े सहयोग से,इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, सरकार का निशाना, समोसा जलेबी कचोरी नहीं बल्कि खाद्य पदार्थों में छिपे,अतिरिक्त चीनी व तेल केहानिकारक सेवन के विकल्प से जागरूक कराना है।

साथियों बात अगर हम तेल चीनी बोर्ड लगाने के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेश/निर्देश को समझनें की करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के मुख्य सचिव ने सभी विभागों को तेल और चीनी बोर्ड लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश, स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने और मोटापे तथा गैर-संचारी रोगों से निपटने के लिए, देश भर के केंद्रीय संस्थानों में लागू किया जाएगा। इन तेल और चीनी बोर्डों नाश्ते में मौजूद वसा और चीनी की मात्रा को दर्शाया जाएगा, जिससे लोगों को जंक फ़ूड के बारे में जानकारी मिल सके।उद्देश्य–इस पहल का मुख्य उद्देश्य, लोगों को उनके दैनिक भोजन में मौजूद वसा और चीनी की मात्रा के बारे में जागरूक करना है, ताकि वे स्वस्थ जीवनशैली अपना सकें।कार्यान्वयन–ये बोर्ड, स्कूलों, कार्यालयों, सार्वजनिक संस्थानों और कैंटीन में लगाए जाएंगे, ताकि लोगों को इन खाद्य पदार्थों के हानिकारक प्रभावों के बारे में जानकारी मिल सके।डिजिटल डिस्प्ले–कुछ संस्थानों में, इन बोर्डों को डिजिटल रूप से प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके।अन्य उपाय–इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों को आधिकारिक स्टेशनरी और प्रकाशनों पर स्वास्थ्य संदेश छापने का भी निर्देश दिया है, ताकि मोटापे से लड़ने के लिए दैनिक अनुस्मारक दिया जा सके।स्वस्थ भोजन को बढ़ावा– मंत्रालय ने कार्यालयों में स्वस्थ भोजन विकल्पों को बढ़ावा देने और शारीरिक गतिविधि को प्रोत्साहित करने के लिए भी कदम उठाए हैं, जैसे कि सीढ़ियों का उपयोग करने और पैदल चलने के मार्गों की सुविधा प्रदान करना फिट इंडिया मूवमेंट–यह पहल,फिट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। साथियों बात अगर हम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारासभी मंत्रालयों को लिखे पत्र की करें तो, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों को हाल ही में लिखे एक पत्र में कहा की, हम विभिन्न स्थानों पर स्वस्थ आहार संबंधी आदतों को बढ़ावा देने के लिए चीनी और तेल बोर्ड पहल का प्रदर्शन करने का प्रस्ताव दिए जा रहे हैं। ये बोर्ड स्कूलों, कार्यालयों, सार्वजनिक संस्थानों आदि में रोज़मर्रा के खाद्य पदार्थों में छिपे वसा और चीनी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदर्शित करते हुए दृश्य व्यवहारिक संकेत के रूप में काम करेंगे। यह अभियान सबसे पहले नागपुर में शुरू किया जा रहा है, जहाँ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) इस पहल के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में काम करेगा।स्वस्थ विकल्पों को प्रोत्साहित करते हुए,सरकारी विभागों से मोटापे से लड़ने के दैनिक अनुस्मारक को सुदृढ़ करने के लिए सभी आधिकारिक स्टेशनरी और प्रकाशनों पर स्वास्थ्य संदेश छापने का अनुरोध किया। अपने पत्र में, स्वास्थ्य सचिव ने द लैंसेट में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन का हवाला दिया, जिसमें अनुमान लगाया गया था कि 2050 तक लगभग 45 करोड़ भारतीय अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हो सकते हैं। इसका मतलब है कि सदी के मध्य तक, चीन के बाद, भारत में दुनिया में दूसरे सबसे अधिक अधिक वजन और मोटे लोग होने की संभावना है। नागपुर में अब लोकप्रिय फ़ूड स्टॉल्स के पास कैलोरी काउंट पोस्टर लगा होगा, जिसमें चीनी, वसा और ट्रांस-फ़ैट की मात्रा के बारे में स्पष्ट जानकारी होगी। इसमें बार-बार सेवन से होने वाले दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिमों की रूपरेखा होगी। ये चेतावनियाँ प्रत्यक्ष और जागरूकता पैदा करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। इसका उद्देश्य संयम को बढ़ावा देना है, प्रतिबंध को नहीं। इस अभियान का इस साल के अंत में अन्य शहरों में विस्तार होने की उम्मीद है और हमें उम्मीद है कि यह कदम लोगों को अधिक सोच-समझकर भोजन चुनने के लिए प्रोत्साहित करेगा।समोसे, पकौड़े, चाय-बिस्कुट या जलेबी में कितना तेल, चीनी और ट्रांस फैट मौजूद है? इसकी जानकारी अब आपको मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी सरकारी विभागों से अपने कैफेटेरिया, लॉबी और मीटिंग रूम में ऐसी जानकारी प्रदर्शित करने के निर्देश दिए है। यह जानकारी लोकप्रिय भारतीय स्नैक्स के स्वास्थ्य जोखिमों को उजागर करने के लिए है, खासकर ऐसे समय में जब देश भर में जीवनशैली से जुड़ी बीमारियाँ तेजी से बढ़ती जा रही हैं।

साथियों बात अगर हम वर्तमान खास परिवेश के संबंध में डब्लूएचओ के विचारों की करें तो, एक नए अध्ययन से पता चलता है कि भारत में मधुमेह का प्रमुख कारण अति-प्रसंस्कृत और फास्ट फूड का सेवन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि वर्तमान खाद्य परिवेश, जिसमें बहुत से लोग रहते हैं, काम करते हैं और अपना दैनिक जीवन व्यतीत करते हैं, में अत्यधिक प्रसंस्कृत और आसानी से उपलब्ध खाद्य पदार्थ शामिल हैं जिनमें अस्वास्थ्यकर वसा, शर्करा और सोडियम की मात्रा अधिक होती है। इनमें से कई खाद्य पदार्थों का विपणन भी बहुत अधिक होता है और वे अपेक्षाकृत सस्ते भी होते हैं।परिणामस्वरूप, उपभोक्ताओं को अक्सर स्वस्थ भोजन से संबंधित निर्णय लेने में चुनौती का सामना करना पड़ता है। अस्वास्थ्यकर आहार अब वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम में अग्रणी, मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग, स्ट्रोक और कैंसर सहित गैर-संचारी रोगों में योगदान दे रहा है।

साथियों बात अगर हम सीबीएसई द्वारा अपने सभी स्कूलों में तेल बोर्ड लगाने के आदेश की करें तो, देश में बढ़ते मोटापे को देखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार को सीबीएसई के निदेशक ने सभी स्कूल प्रमुखों को पत्र लिखकर निर्देश दिया कि वे अपने स्कूलों में 'ऑयल बोर्ड' लगाएं और छात्रों के बीच स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा दें। यह कदम 14 मई 2025 को जारी 'शुगर बोर्ड' से संबंधित सर्कुलर का ही विस्तार है।

जिम्मेदार कौन ?

प्रिय पाठकों आप भी एक पत्रकार हो तथा **दैनिक इंडिया वार्ता** की आवाज बन सकते हैं। बस आपको इसके लिए जरूरत है कि हर समय अपनी आंख व कान खुली रखें। चौंकन्ने रहें कि आपके चारों ओर क्या कुछ घटित हो रहा है। नाबालिग बच्चे ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं? स्कूल बंक कर रहे हैं? विकास कार्यों में गड़बडी हो रही है? निर्माण कार्य महीनों से अधूरे पड़े हैं, पाइप लाइन टूटी हैं, घरों में दूषित पेयजल आपूर्ति या महिनों से पानी नहीं आ रहा है। मनरेगा में धांधली हो रही है? आपकी इस प्रकार की समस्याओं को **दैनिक इंडिया वार्ता** जिम्मेदार कॉलम में प्रमुखता के साथ उठाएगा? बस आप उठाइए कलम और तुरंत लिखकर हमें भेजें या फिर संपर्क करें? आपकी आवाज को सत्ता के शीर्ष में बैठे लोगों एवं सम्बन्धित अधिकारी तक पहुंचाया जाएगा तथा इन समस्याओं को जल्द से जल्द हल कराने का प्रयास भी किया जाएगा।

संपर्क करें

संपादक

दैनिक इंडिया वार्ता

प्रधान कार्यालय : मोहक्कमपुर खुर्द पोस्ट आई.आई.पी. रेलवे क्रसिंग हरिद्वार रोड़ देहरादून (उत्तराखण्ड)

मोबाईल न.- 7500581414,9359555222

Email: indiawarta@gmail.com

जनहित में त्वरित फैसले: देहरादून जिला प्रशासन का सराहनीय कदम

इंडिया वार्ता ब्यूरो

देहरादून । देहरादून जिला प्रशासन ने एक बार फिर जनहित को प्राथमिकता देते हुए त्वरित निर्णय लेने की अपनी पहचान को कायम रखा है। जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में आयोजित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारियों की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई की गई।

बैठक में 15 मिनट की देरी से पहुंचने पर जिलाधिकारी ने स्वयं क्षमा याचना की, जिसका कारण बुजुर्ग याचियों से उनकी मुलाकात थी। यह दर्शाता है कि प्रशासन जनता की समस्याओं के प्रति कितना संवेदनशील है।

बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णयों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारियों को कल से ही स्मार्ट सिटी की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा शामिल है। इसके अतिरिक्त, जिलाधिकारी ने रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा के लिए भी पत्राचार का आश्वासन दिया।

आवास हेतु भूखंड आवंटन के संबंध में जिलाधिकारी ने मेयर नगर निगम से दूरभाष पर व्यक्तिगत अनुरोध किया और 100 वर्ग मीटर भूमि आवंटन के लिए हरसंभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। पुरानी जजी कलेक्टरेट परिसर में निर्माणाधीन सेनानी भवन में उत्पन्न विवाद को भी जिलाधिकारी ने मौके पर ही सुलझाया।

स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारकों और शिलापटों के संरक्षण को सभी विभागों की प्राथमिक जिम्मेदारी बताते हुए, पुरानी जेल परिसर स्थित स्मारकों के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए तत्काल स्वीकृति प्रदान की गई। बांगखाला में स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर द्वार निर्माण के लिए एमडीडीए को निर्देश दिए गए।

सबसे महत्वपूर्ण, 10 उत्तराधिकारियों के पेंशन एरियर का भुगतान आज ही करने का आदेश मुख्य कोषाधिकारी को दिया गया, जिस पर तत्काल अमल किया गया। रोडवेज बसों के कंडक्टरों द्वारा अभद्रता की शिकायत पर उन्हें प्रशिक्षित करने के निर्देश भी दिए गए।

चिकित्सालयों में स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों और बुजुर्ग नागरिकों के लिए अलग पंजीकरण और सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए गए। इन सभी त्वरित और प्रभावी निर्णयों ने जिला प्रशासन की जनहितैषी छवि को और मजबूत किया है।

आईटीबीपी इंस्पेक्टर का शस्त्र लाइसेंस निलंबित, परिवार को धमकाने पर डीएम का कड़ा एक्शन

इंडिया वार्ता ब्यूरो

देहरादून । देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने एक आईटीबीपी इंस्पेक्टर का शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

इंस्पेक्टर पर अपने बेटे और पूर्व पत्नी को लाइसेंसी बंदूक से धमकाने का आरोप था, जिससे उनके जीवन को खतरा बताया जा रहा था। जिलाधिकारी ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए यह सख्त कदम उठाया और पुलिस को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर हथियार जब्त करने के आदेश दिए हैं।

क्या था मामला ?

दरअसल, हाल ही में आयोजित जनता दिवस में रेसकोर्स निवासी विकास घिल्डियाल ने जिलाधिकारी को एक गंभीर शिकायत दर्ज कराई थी। विकास ने बताया कि उनके माता-पिता का तलाक हो चुका है, लेकिन उनके पिता, जो कि एक आईटीबीपी इंस्पेक्टर हैं, अपनी लाइसेंसी बंदूक का इस्तेमाल उन्हें और उनकी माता को डराने-धमकाने के लिए करते हैं। विकास ने आशंका जताई थी कि इससे कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है। सगे बेटे और पूर्व पत्नी के लिए ही खतरा बने इस शस्त्र लाइसेंस पर जिलाधिकारी ने गंभीरता से संज्ञान लिया।

डीएम का तत्काल और कड़ा एक्शन

शिकायत सुनते ही जिलाधिकारी सविन बंसल ने मौके पर ही तत्काल कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर के शस्त्र लाइसेंस को निलंबित करने का आदेश दिया। साथ ही, उन्होंने एसएसपी को संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और शस्त्र को तत्काल थाने में जमा करवाने के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी के इस निर्णय से जहां पीड़ित माता और पुत्र ने राहत की सांस ली है, वहीं शस्त्र लाइसेंस का दुरुपयोग करने वालों को भी प्रशासन की ओर से एक सख्त संदेश मिला है।

"लाइसेंस का मतलब मनमर्जी की छूट नहीं": जिलाधिकारी

जिलाधिकारी बंसल ने स्पष्ट संदेश दिया कि लाइसेंस का मतलब मनमर्जी की छूट नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि कोई लाइसेंस धारक नियमों और मर्यादाओं का पालन नहीं करता है और अपने हथियार का दुरुपयोग करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है। जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा के लिए जारी किए गए शस्त्र लाइसेंस का उपयोग किसी को धमकाने या डराने के लिए नहीं किया जा सकता, और ऐसी किसी भी घटना पर प्रशासन कड़ा रुख अपनाएगा।

सैकड़े के करीब पंहुचा रक्तवीर उत्तराखंड पुलिस का जवान "शाहनवाज़"

82 बार रक्तदान कर फिर बचाई एक जान,रक्तदान करते करते देहरादून पुलिस महकमे की शान बन चूका है शाहनवाज़!

देहरादून,इंडिया वार्ता ब्यूरो । कहते है की अपने घर की शादी मे हज़ारो लोग इक्क्ठे हो जाते है लेकिन अगर बीमारी मे एक बॉटल खून की जरूरत पड़ जाये तो अंगुली पर गिने जाने वाले लोग भी टाइम पर नहीं पहुंचते लेकिन उत्तराखंड पुलिस की शान बन चूका शानवाज़ किसी की जान बचाने के अवसर को भूले से भी नहीं भूलता शाहनवाज़ को अगर किसी भी माध्यम से यह पता चल जाये की किसी जरुरतमंद को खून की दरकार है तो वाह ज़िंन की तरह से वहां पहुंच कर खून दे कर वापस लौट आता है ताज़ा मामला यह है की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आफिस मे तैनात शाहनवाज़ को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ग्राफिक ऐरा हॉस्पिटल में उपचाराधीन व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता के सम्बंध में सूचना मिली तो किसी भी अपरिहार्य स्थिति अथवा संकट की घडी में सदैव आमजन की सेवा हेतु तत्पर रहने वाली उत्तराखंड पुलिस द्वारा एक बार फ़िर मित्रता, सेवा, सुरक्षा के मूल मंत्र को चरित्रार्थ करते हुए अपने मानवता के कर्तव्यों को अंजाम देने की मिसाल पेश कर दी आपको बता दे की दिनाँक = 16-07-25 व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राफिक ऐरा हॉस्पिटल देहरादून में उपचाराधीन एक व्यक्ति को रक्त की नितांत आवश्यकता है, जिस पर एस एस पी ऑफिस देहरादून में नियुक्त कॉ0 शाहनवाज द्वारा तत्काल ग्राफिक ऐरा हॉस्पिटल जाकर स्वेच्छा से रक्तदान करते हुए उपचाराधीन व्यक्ति की सहायता करते हुए उत्तराखंड पुलिस के मानवता के कर्तव्यों का निर्वहन किया गया।

राजेंद्र नगर टर्मिनल से नई दिल्ली के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ

नियमित सेवा दिनांक 31.07.2025 से राजेंद्र नगर टर्मिनल से तथा 01.08.2025 से नई दिल्ली से प्रतिदिन चलेगी

रेल यात्रियों के सुविधाजनक आवागमन हेतु , रेलवे ने राजेंद्र नगर टर्मिनल और नई दिल्ली के बीच एक नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी संख्या 22361/22362 का संचालन करने का निर्णय लिया है। इस रेलगाड़ी की उद्घाटन सेवा दिनांक 18.07.2025 को राजेंद्र नगर टर्मिनल से तथा दिनांक 19.07.2025 को नई दिल्ली से चलेगी । राजेंद्र नगर टर्मिनल- नई दिल्ली - राजेन्द्र नगर अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी की उद्घाटन सेवा तथा नियमित सेवा की समय सारणी निम्नानुसार है :-

- रेलगाड़ी संख्या 03261 राजेंद्र नगर टर्मिनल - नई दिल्ली अमृत भारत उद्घाटन स्पेशल दिनांक 18.07.2025 को

समय - सारणी

स्टेशन	03261 राजेंद्र नगर टर्मिनल - नई दिल्ली अमृत भारत उद्घाटन स्पेशल रेलगाड़ी	
	आगमन	प्रस्थान
राजेंद्र नगर टर्मिनल	----	11:45
पटना जं	12:00	12:10
दानापुर	12:30	12:35
आरा जंक्शन	13:15	13:20
बक्सर	14:10	14:15
पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन	15:40	15:50
सूबेदारगंज	18:15	18:20
गोविन्दपुरी जंक्शन	20:50	20:55
गाज़ियाबाद जंक्शन	02:40	02:45
नई दिल्ली	04:00	-----

- रेलगाड़ी संख्या 03262 नई दिल्ली - राजेंद्र नगर टर्मिनल अमृत भारत उद्घाटन स्पेशल दिनांक 19.07.2025 को

समय-सारणी

स्टेशन	03262 नई दिल्ली - राजेंद्र नगर टर्मिनल उद्घाटन स्पेशल रेलगाड़ी	
	आगमन	प्रस्थान
नई दिल्ली	-----	1800
गाज़ियाबाद जंक्शन	1838	1840
गोविन्दपुरी जंक्शन	0025	0030
सूबेदारगंज	0300	0305
पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन	0715	0725
बक्सर	0840	0845
आरा जंक्शन	0935	0940
दानापुर	1020	1025
पटना जं	1050	1100
राजेंद्र नगर टर्मिनल	1145	-----

संयोजन:- शयनयान व सामान्य श्रेणी

- रेल गाड़ी संख्या 22361/22362 राजेंद्र नगर टर्मिनल - नई दिल्ली - राजेंद्र नगर टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी की नियमित सेवा का संचालन

समय- सारणी

गाड़ी संख्या 22361 राजेंद्र नगर टर्मिनल - नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस की नियमित सेवा दिनांक 31.07.2025 से प्रतिदिन		↑ स्टेशन ↓	गाड़ी संख्या 22362 नई दिल्ली - राजेंद्र नगर टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस की नियमित सेवा दिनांक 01.08.2025 से प्रतिदिन	
आगमन	प्रस्थान		आगमन	प्रस्थान
----	19:45	राजेंद्र नगर टर्मिनल	1145	----
2000	2010	पटना जं	1050	1100
2023	2025	दानापुर	1028	1030
2054	2056	आरा जंक्शन	0955	0957
2138	2140	बक्सर	0858	0900
2335	2345	पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन	0740	0750
0200	0205	सूबेदारगंज	0300	0305
0425	0430	गोविन्दपुरी जंक्शन	0025	0030
1223	1225	गाज़ियाबाद जंक्शन	1946	1948
1310	----	नई दिल्ली	----	1910

तुम उसके बुलाने पर होटल क्यों जाती थी, रेप का आरोप लगाने वाली महिला पर भड़का सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली,एंजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महिला से शादी का वादा कर उसके साथ यौन संबंध बनाने के आरोप में व्यक्ति की अग्रिम जमानत बरकरार रखी। वहीं, कोर्ट ने महिला को फटकार लगाते हुए कहा कि उसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाकर अपराध किया है। अदालत ने महिला को यह भी चेतावनी दी कि शादी के दौरान अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाने पर उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, याचिका पर जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने महिला को चेताया है कि विवाहित होते हुए पति के अलावा किसी और शख्स से संबंध बनाए जाने के चलते उसपर भी मुकदमा चलाया जा सकता है। साथ ही कहा है कि उसने विवाह के बाहर रिश्ता बनाकर अपराध किया है। महिला की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील ने कहा कि शख्स महिला के साथ शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाता रहा। इसपर कोर्ट ने महिला से कहा, %आप एक शादीशुदा महिला हैं और आपके दो बच्चे हैं। आप मेच्योर हैं और आप समझते हैं कि जो रिश्ता आप बनाने जा रहे हैं वह शादी के बाहर बना रहे हैं।' वकील ने यह भी कहा कि शख्स ने महिला को शारीरिक संबंध बनाने के लिए कई बार होटल बुलाया था। कोर्ट ने कहा, %आप उसके अनुरोध पर बार-बार होटल क्यों गए थे? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपने भी शादी के बाहर शारीरिक संबंध रखकर अपराध किया है।'

बता दें कि महिला और आरोपी शख्स की मुलाकात साल 2016 में सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। तब से ही दोनों रिलेशन में हैं। महिला के आरोप थे कि उसने साथी के दबाव में आकर पति से तलाक लिया था, जिसपर फैमिली कोर्ट ने भी 6 मार्च को मुहर लगा दी थी। तलाक के तुरंत बाद महिला ने उससे शादी करने के लिए कहा, तो उसने मना कर दिया। इस बात से खफा होकर महिला ने बिहार पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आरोप लगाए कि शख्स ने उसके साथ शादी का झूठा वादा कर यौन उत्पीड़न किया है। बाद में जब मामला कोर्ट पहुंचा, तो पटना हाईकोर्ट ने शख्स को जमानत दे दी। हाईकोर्ट ने पाया था कि महिला के तलाक के बाद से ही दोनों किसी शारीरिक गतिविधियों में नहीं रहे हैं।

अशोक गहलोत का अमित शाह पर हमला, कन्हैयालाल के हत्यारों को अब तक सजा क्यों नहीं ?

जयपुर ,एंजेंसी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के जयपुर दौरे को लेकर उन पर तीखा हमला बोला है। अपने निवास पर मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर अमित शाह से जवाब मांगा। उन्होंने पूछा कि जिस घटना का दुष्प्रचार करके भाजपा राजस्थान की सत्ता में आई, उस घटना के हत्यारों को अब तक सजा क्यों नहीं मिली। गहलोत ने कहा कि कन्हैयालाल की हत्या एक बेहद मार्मिक घटना थी, जिसने पूरे देश को हिला दिया था। उनकी सरकार ने चार घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बावजूद, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) ने उसी रात केस अपने हाथ में ले लिया, जिस पर उनकी सरकार ने कोई आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि तीन साल बीत जाने के बाद भी एनआईए कोर्ट में जज नहीं बैठते, जिससे सुनवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है। गहलोत ने सवाल उठाया, परिवार और प्रदेशवासी न्याय मांग रहे हैं, उन्हें न्याय कब मिलेगा?

पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा पर चुनाव में इस घटना को मुद्दा बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जानबूझकर यह झूठ फैलाया कि उनकी सरकार ने कन्हैयालाल के परिवार को ?5 लाख और एक मुस्लिम परिवार को ?50 लाख दिए हैं। गहलोत ने स्पष्ट किया कि कन्हैयालाल के परिवार को ?50 लाख का पैकेज दिया गया था, जो आजादी के बाद दिया गया सबसे बड़ा पैकेज था। उन्होंने कहा कि इस झूठ के कारण चुनाव में कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ और प्रदेशवासी भाजपा को इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगे।

गहलोत ने अमित शाह से पूछा कि अगर यह केस राजस्थान सरकार, एसओजी या एटीएस के पास होता, तो अब तक आरोपियों को सजा मिल चुकी होती। उन्होंने बताया कि घटना के बाद उनकी सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, जिससे उदयपुर में कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं हुआ और पूरे देश में सरकार की तारीफ हुई। उन्होंने भाजपा नेताओं पर आरोप लगाया कि वे उस वक्त हैदराबाद में अपनी मीटिंग में व्यस्त थे और उन्हें उदयपुर की स्थिति की कोई चिंता नहीं थी।

गहलोत ने अमित शाह से आग्रह किया कि वह राजस्थान की जनता को बताएं कि कन्हैयालाल के परिवार को न्याय कब मिलेगा। उन्होंने कहा कि कई मामलों में छह महीने के भीतर ही फैसले हो जाते हैं, लेकिन इतने गंभीर केस में तीन साल बाद भी कुछ नहीं हुआ है, जो निराशाजनक है।

बालासोर छात्रा आत्मदाह मामले में ओडिशा बंद का ऐलान, कई जगहों पर चक्का जाम, ये सेवाएं रहेंगी बंद

भुवनेश्वर ,एंजेंसी। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में गुरुवार को कांग्रेस के नेतृत्व में 8 विपक्षी दलों ने 12 घंटे के ओडिशा बंद का आह्वान किया है। यह बंद बालासोर की फकीर मोहन स्वायत्त कॉलेज की छात्रा की आत्मदाह के विरोध में और महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के खिलाफ बुलाया गया है। सुबह 6 बजे से शुरू हुए इस बंद के कारण शहर में बसों का परिचालन ठप है, दुकानें बंद हैं, और राष्ट्रीय राजमार्ग 16 सहित मास्टर कैंटीन चौक (जो राज्य सचिवालय, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे से जुड़ा हुआ है) पर प्रदर्शनकारी चक्काजाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं।

इससे सड़कों पर पूरी तरह से आवागमन बाधित हो गया है। प्रदर्शनकारी बालासोर में फकीर मोहन स्वायत्त कॉलेज की 20 वर्षीय छात्रा की आत्मदाह की घटना में कड़ी कार्रवाई और उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यबंशी सूरज के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

सीपीआईएम (लिबरेशन) के नेता महेंद्र परिदा ने कहा कि छात्रा ने कई बार मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, स्थानीय विधायक और सांसद से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बताया कि कॉलेज की आंतरिक शिकायत समिति ने आरोपी प्रोफेसर समीर साहू को बर्खास्त करने की सिफारिश की थी, लेकिन प्राचार्य ने इसका विरोध किया और समझौते का दबाव बनाया। परिदा ने तीन प्रमुख मांगें रखीं, जिनमें उच्च शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, घटना की न्यायिक जांच और सभी दोषियों को सख्त सजा शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ओडिशा में पिछले एक साल में भाजपा सरकार के शासन में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अत्याचार बढ़े हैं और सरकार इसकी अनदेखी कर रही है। ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रदीप महापात्रा ने कहा कि आठ दलों का गठबंधन शांतिपूर्ण तरीके से बंद का आयोजन कर रहा है। उन्होंने बताया कि लोग इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। महापात्रा ने कहा कि सरकार को अपनी कार्यशैली सुधारनी चाहिए और लोगों के हित में काम करना चाहिए। हालांकि, इस बंद से छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भुवनेश्वर में एक छात्र ने बताया कि आज उनकी प्रैक्टिकल परीक्षा थी, लेकिन बंद के कारण उन्हें परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है। छात्र ने कहा, हमें पांच किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ रहा है, क्योंकि कोई सवारी उपलब्ध नहीं है। कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआई(एम), सीपीआईएमएल, फॉरवर्ड ब्लॉक, सपा, राजद और एनसीपी जैसे दलों ने इस बंद को समर्थन दिया है। सुबह 6 बजे से शुरू हुआ बंद शाम 6 बजे तक चलेगा। प्रदर्शनकारी सरकार से महिलाओं की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं।

बिहार में अब हर महीने 125 यूनिट बिजली फ्री, चुनाव से पहले CM नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान

पटना । बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले आम जनता को बड़ी राहत दी है। उन्होंने घोषणा की है कि 1 अगस्त 2025 से राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। उपभोक्ताओं को जुलाई माह के बिल से ही इसका लाभ मिलने लगेगा।

मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी, हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब तय कर लिया गया है कि घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली पर कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इस योजना से करीब 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा, खासकर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को। इसके अलावा नीतीश कुमार ने कहा कि आने वाले तीन वर्षों में राज्य सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देगी। उपभोक्ताओं की सहमति से घर की छतों या पास के सार्वजनिक स्थलों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। कुटीर ज्योति योजना के तहत अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। बाकी उपभोक्ताओं को भी सरकार द्वारा वित्तीय सहयोग दिया जाएगा। सरकार का अनुमान है कि इन प्रयासों से आने वाले वर्षों में राज्य को 10,000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा मिल सकेगी, जिससे बिजली संकट काफी हद तक खत्म होगा।

सल्ट ब्लॉक कांग्रेस ने जिला पंचायत प्रत्याशियों का किया ऐलान, धीरेंद्र प्रताप ने जताई ऐतिहासिक जीत की उम्मीद

इंडिया वार्ता ब्यूरो

मरचूला/अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जनपद में आगामी जिला पंचायत चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में, सल्ट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार को सर्वसम्मति से पांच जिला पंचायत सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया।

इस महत्वपूर्ण बैठक में उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, वरिष्ठ प्रवक्ता, पूर्व मंत्री और अल्मोड़ा जनपद के जिला पंचायत चुनाव प्रभारी धीरेंद्र प्रताप मुख्य रूप से मौजूद रहे।

मरचूला स्थित सल्ट विकास खंड केंद्र में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता सल्ट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह रावत ने की। धीरेंद्र प्रताप ने सभी पार्टी नेताओं से गहन विचार-विमर्श करने के बाद और

शीर्ष नेतृत्व से संपर्क साधकर उम्मीदवारों की अंतिम घोषणा की।

पार्टी द्वारा घोषित प्रत्याशियों में श्रीमती पुष्पा देवी को नेकणा से और श्रीमती पूजा वोरा को घचकोट से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं, श्री प्रहलाद सिंह को पनुवादेखन से पार्टी का समर्थन मिला है। इन प्रत्याशियों को पार्टी के व्यापक समर्थन का लाभ मिलेगा।

हालांकि, उजराड और अजोली तल्ली की दो सीटों पर पार्टी ने फिलहाल सीधा प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। उजराड जिला पंचायत क्षेत्र में जहां शिवेंद्र रावत और मनमोहन सिंह बंगारी जैसे दो मजबूत उम्मीदवार मैदान में हैं, वहीं अजोली तल्ली से श्री शंभू सिंह रावत और श्री रवि चोपड़ा दावेदार हैं। इन दोनों सीटों को चुनाव के लिए 'ओपन' छोड़ दिया गया है, जिसका अर्थ है कि पार्टी यहां सभी दावेदारों को मौका देगी।

इस मौके पर धीरेंद्र प्रताप ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अल्मोड़ा जनपद ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड में जिला पंचायत के चुनाव अत्यंत मजबूती से लड़ रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भाजपा के "कुशासन, भ्रष्टाचार, महंगाई और विकास की कुल विफलता" जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी और आगामी चुनावों में पार्टी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी।

बैठक में पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्री नारायण सिंह रावत, पौड़ी गढ़वाल के नैनी डांडा कांग्रेस के अध्यक्ष मनीष सुंदरलाल, शंभू सिंह रावत सहित दो दर्जन से अधिक वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। सभी ने पार्टी प्रत्याशियों के चयन पर सर्वसम्मति से अपनी सहमति जताई।

बाद में पत्रकारों से बातचीत में धीरेंद्र प्रताप ने दृढ़ता से कहा कि कांग्रेस इस चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल करेगी और भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कांग्रेस की जीत को लेकर पूरा भरोसा जताया।

फायर स्टेशन रानीखेत ने नाले में गिरी गाय को सुरक्षित बाहर निकाल कर बचाई जान

अल्मोड़ा (इंडिया वार्ता ब्यूरो)। आज दिनांक 17.07.2025 को फायर स्टेशन रानीखेत को सूचना मिली कि राय स्टेट रानीखेत के पास एक गाय सड़क किनारे नाले में गिर गई है। जिस पर फायर सर्विस यूनिट रानीखेत तत्काल एफएसएसओ रानीखेत के नेतृत्व में घटनास्थल पर पहुंची। फायर सर्विस यूनिट ने स्थानीय लोगों की सहयोग से सड़क किनारे नाले में गिरी गाय को रस्से से बांधकर बाहर निकाला गया। तत्पश्चात् पशु चिकित्सक को बुलाकर उपचार कराया गया।

फायर सर्विस रानीखेत टीम-

1-लिडिंग फायर मैन श्री नरेश जोशी 2-चालक श्री उत्तम सिंह 3-फायरमैन श्री अरविंद कुमार 4-फायरमैन श्री विक्रांत सिंह

जिला न्यायालय परिसर में हरेला महोत्सव के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण

अल्मोड़ा (इंडिया वार्ता ब्यूरो)। माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशन एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अल्मोड़ा के मार्गदर्शन में दिनांक 17/07/2025 को हरियाली के प्रतिक "हरेला महोत्सव" के अवसर पर 1 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक वृक्षारोपण अभियान के अनुक्रम में माननीय जनपद न्यायाधीश /अध्यक्ष, महोदय श्री श्रीकांत पाण्डेय जी द्वारा जिला न्यायालय परिसर में फलदार, छायादार, औषधीय व अन्य वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया। श्रीमती नीना अग्रवाल परिवार न्यायालय न्यायाधीश, सुश्री शचि शर्मा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा, श्री रविन्द्र देव मिश्र सिविल जज (सीनियर डिवीजन), श्रीमती उड़ीशा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) व श्री नवल न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा भी वृक्षारोपण किया गया।उपस्थित व्यक्तियों को वृक्षों के महत्व व पर्यवरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया।उक्त अवसर पर अधिवक्ताओं, कर्मचारियों एवं अधिकार मित्रों द्वारा भी वृक्षारोपण किया गया।

त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025: मतदान अधिकारी प्रथम का पहला प्रशिक्षण हुआ आयोजित

इंडिया वार्ता ब्यूरो

अल्मोड़ा । त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025 की तैयारियों के अंतर्गत आज गठित पोलिंग पार्टियों का सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण उदय शंकर नाट्य अकादमी एवं एसएसजे विवि लोवर कैंपस के ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला प्रशासन द्वारा सुनियोजित रूप से सम्पन्न किया गया, जिसमें मतदान प्रक्रिया से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी एवं व्यवहारिक अभ्यास कराया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय ने प्रतिभाग करते हुए मतदान कार्मिकों को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को निर्वाचन से संबंधित नियमों, प्रक्रियाओं एवं मतपेटियों, मतपत्र समेत चुनाव के संचालन की बारीकियों से अवगत कराते हुए उन्हें पूरी गंभीरता से प्रशिक्षण लेने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रत्येक कार्मिक को निर्वाचन की पूरी जानकारी हो, जिससे आगामी पंचायत चुनाव निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। इस अवसर पर मास्टर ट्रेनरों ने मतदान की प्रक्रिया, प्रपत्रों की भराई, पोलिंग पार्टी की जिम्मेदारियों एवं मतगणना से पूर्व की जाने वाली तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

इस प्रशिक्षण में कुल 360 पोलिंग पार्टियों का प्रशिक्षण हुआ। प्रत्येक पोलिंग पार्टी में पीठासीन अधिकारी समेत 5 मतदान कार्मिक सम्मिलित हैं। इस प्रकार कुल 1800 कार्मिकों का आज सैद्धांतिक एवं व्याहारिक प्रशिक्षण हुआ।

इस प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर अपर सांख्यिकी अधिकारी अशोक कुमार, प्रवक्ता डायट डॉ हेम जोशी, जिला समन्वयक समग्र शिक्षा नीरज जोशी, प्रवक्ता कपिल नयाल, विनोद राठौर तथा अन्य ने सभी कार्मिकों को चुनाव सम्बन्धी विभिन्न बारीकियां बताई ।

राजभवन में धरने पर बैठे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा गिरफ्तार

देहरादून,इंडिया वार्ता ब्यूरो । राज्य में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर इतनी अधिक अनियमितताओं और अनिश्चितताओ का सामना करना पड़ रहा है कि उनका कोई अंत होता नहीं दिख रहा है। लोग हाईकोर्ट की चौखट पर तमाम मामलों को लेकर खड़े हैं वहीं चुनाव आयोग समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा है। रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा जिन प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों को जांच में रद्द कर दिया गया उनमें से आधा दर्जन के आसपास प्रत्याशियों को हाई कोर्ट द्वारा योग्य ठहराया जा चुका है ऐसे में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचन आयोग की कार्य प्रणाली से क्षुब्ध होकर तथा राजभवन से समय न मिलने से नाराज होकर राज भवन पर गुरूवार को धरने पर बैठ गए जहां से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वह निर्वाचन आयुक्त को बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे जिन्हें पुलिस ने बाद में पुलिस लाइन ले जाकर छोड़ दिया गया। हाई कोर्ट पहुंचे कई प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों को आर ओ द्वारा गलत तरीके से रद्द किया जाना पाया गया है। चुनाव आयोग अब तक ऐसे कुछ आर ओ के खिलाफ कार्यवाही भी कर चुका है चुनाव आयोग अपनी कार्यशैली और गलत निर्णयों के कारण सुर्खियों में बना रहा है। बात चाहे दोकृदो सूचियों में मतदाता होने को लेकर हो या फिर नामांकन पत्रों की जांच को लेकर जिम्मेवारी तो वह चुनाव आयोग की है। अभी तक हाई कोर्ट के आदेश पर चुनाव के योग्य ठहराए गए कई प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह वितरित नहीं किये जा रहे हैं जिनके नामांकन पत्रों को कोर्ट से सही ठहराया जा चुका है।

भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी ने पिंक ड्रेस में ढाया कहर, इंस्टाग्राम पर शेयर की हॉट तस्वीरें

भोजपुरी और टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट से सोशल मीडिया का तापमान बढ़ा दिया है. आकांक्षा ने पिंक कलर की खूबसूरत लेस ड्रेस पहनकर अपनी कुछ हॉट तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, जिनमें उनका बोल्ड और ग्लैमरस अंदाज देखते ही बनता है. एक्ट्रेस ने पोस्ट में लिखा, गुलाबी रंग के हर टांके में रोमांस. फोटोज में आकांक्षा का कॉन्फिडेंट पोज, सॉफ्ट कर्ल हेयरस्टाइल और मिनिमल मेकअप उनके लुक को और भी एलिगेंट बना रहा है. पिंक ड्रेस के साथ मैचिंग नेल पॉलिश और ओपन हेयर ने भी उनके ग्लैम लुक में चार चांद लगा दिए हैं. फैंस उनकी इन तस्वीरों पर दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं और कमेंट सेक्शन में फायर और हार्ट इमोजी की बारिश कर रहे हैं.

कुछ ही घंटों में इन तस्वीरों को हजारों लाइक्स मिल चुके हैं. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उन्हें फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल और स्टनिंग बताते हुए तारीफों के पुल बांधे हैं. आकांक्षा पुरी का यह लेटेस्ट फोटोशूट एक बार फिर साबित करता है कि वह सिर्फ एक शानदार एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि एक फैशन दीवा भी हैं, जिनका हर लुक सोशल मीडिया पर छा जाता है. आकांक्षा पुरी का ये अंदाज यह भी दिखाता है कि वह अपने फैशन सेंस से हर बार फैंस को सरप्राइज करना जानती हैं. उनके हर लुक में एक खास कॉन्फिडेंस और स्टाइल नजर आता है, जो उन्हें बाकी से अलग बनाता है और यही वजह है कि उनकी हर तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो जाती है.

यूपी के सैफई में केदारनाथ शैली का मंदिर बनाने का विरोध

देहरादून,इंडिया वार्ता ब्यूरो । उत्तराखंड चार धाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत ने यूपी सैफई इटावा में केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति और नाम से मंदिर बनाए जाने का विरोध किया। महापंचायत महासचिव बृजेश सती ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को सख्त कानून बनाया है। इसके बावजूद इटावा में मंदिर बन कर तैयार भी हो गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। कहा कि उत्तराखंड के चार धामों के नाम का उपयोग, इन मंदिरों की प्रतिकृति के अलावा चार धाम के नाम पर ट्रस्ट न बनाने को लेकर, उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की ओर से प्रस्ताव पारित किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया था कि जो भी इसका ऐसा करेगा करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक साल से अधिक का समय होने के बावजूद धरातल पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। पहले दिल्ली, बाद में तेलंगाना और अब यूपी सैफई में केदारनाथ धाम की तरह मंदिर बना दिया गया है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। सैफई में मंदिर के गर्भ ग्रह में लिंग का आकार भी केदारनाथ धाम की तरह का बनाया गया है। कहा कि उत्तराखंड चार धाम तीर्थ महा पंचायत इस बात को लगातार सरकार, शासन, बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के संज्ञान में मामला लाती रही है। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके विरोध में गुरुवार को सभी धामों में विरोध जताया गया।

रेडक्रास द्वारा रूड़की में इंजीनियरों को दिया गया आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण

डॉ0 अनिल वर्मा "सर्टिफिकेट ऑफ एप्रीसिएशन " से सम्मानित

देहरादून,इंडिया वार्ता ब्यूरो । वालंटियर सोसायटी फॉर एंटरप्रोन्योर, एजुकेशन एंड रूरल एक्शन "वीरा फाऊंडेशन" के संस्थापक एवं सीईओ विनोद डोभाल ने कहा कि आपदाओं को रोका नहीं जा सकता परन्तु इनके दुष्प्रभाव को सीमित किया जा सकता है। इसके लिए वैज्ञानिक सोच, पूर्व अनुभवों पर आधारित कुशल प्रबंधन एवं सघन प्रशिक्षण की आवश्यकता है ।

श्री डोभाल प्रदेशीय अभियंता प्रशिक्षण संस्थान, रूड़की उत्तराखंड के सभागार में वीरा फाऊंडेशन द्वारा अभियंताओं के लिए आयोजित विशेष प्रशिक्षण के तहत् सिंचाई विभाग के अभियंताओं को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपदाओं से बहुत अधिक जन धन की हानि होती है। इसे न्यूनतम करने के लिए पूर्व तैयारी व प्रशिक्षण बहुत ही जरूरी है। यूथ रेडक्रास के मास्टर ट्रेनर आपदा प्रबंधन डॉ0 अनिल वर्मा ने प्रशिक्षण में फायर फाईटिंग के तहत आग के प्रकार,आग बुझाने के सिद्धांत तथा रासायनिक अग्निशमन यंत्रों के संचालन का प्रशिक्षण दिया। घायल अथवा रोगियों को मलबे आदि से सुरक्षित निकालकर उपचार हेतु ले जाने के बचाव के आपातकालीन तरीकों के तहत् फ्री हैंड्स तथा रोप रेस्क्यू का प्रशिक्षण , फर्स्ट एड के तहत सीपीआर का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही जन-जागरूकता अभियान के तहत् एनीमिया, थैलेसीमिया , हीमोफीलिया,,सिकल सेल, डेंगू कंट्रोल , रक्तदान एवं रक्तदान करने के लाभ तथा नशामुक्ति के प्रति जागरूक किया गया। प्रदेशीय अभियंता प्रशिक्षण संस्थान, रूड़की के उपनिदेशक (प्रशासन) ई0 सुरेंद्र भण्डारी तथा वीरा फाऊंडेशन के संस्थापक एवं सीईओ विनोद डोभाल ने रेडक्रास द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षण को उच्चस्तरीय बताते हुए मास्टर ट्रेनर डॉ0 अनिल वर्मा को "सर्टिफिकेट ऑफ एप्रीसिएशन" प्रदान करके सम्मानित किया।

पं.ललित मोहन शर्मा परिसर, ऋषिकेश में धूमधाम से आयोजित किया गया हरेला पर्व

ऋषिकेश ,इंडिया वार्ता ब्यूरो । श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के पं.ललित मोहन शर्मा परिसर, ऋषिकेश में नगर निगम, ऋषिकेश एवं परिसर के संयुक्त तत्वाधान में हरेला पर्व धूमधाम से आयोजित किया गया। इस पावन पर्व पर परिसर में वाणिज्य संकाय की ओर जाने वाले मार्ग पर विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटी एवं फूलों के पौधों का रोपण किया गया नगर निगम ऋषिकेश के मेयर शंभू पासवान द्वारा पर्यावरण को संरक्षित करने हेतु छात्र-छात्राओं एवं परिसर के कर्मचारियों का आह्वान किया गया और साथ ही नगर निगम ऋषिकेश की तरफ से परिसर को हरा-भरा बनाने में सहयोग का आश्वासन दिया गया। इस आयोजन में नगर आयुक्त गोपाल राम बेनिवाल, सहायक नगर आयुक्त अमन कुमार, नमामि गंगे जिला परियोजना अधिकारी रविकांत पाण्डेय, सुश्री नीरजा गोयल नीरजा चैरिटेबल ट्रस्ट परिसर के प्रो.वी.एन.गुप्ता, प्रो.दिनेश शर्मा, प्रो. अधीर कुमार का सक्रिय प्रतिभाग रहा हरेला पर्व के वृक्षारोपण कार्यक्रम में परिसर के कर्मचारीगण श्रीमती शंकुन्तला शर्मा प्रशासनिक अधिकारी, शैलेन्द्र डंगवाल, श्रीमती विजया भट्ट, सुरेन्द्र नौड़ियाल, श्रीमती श्वेता, श्रीमती प्रियंका दुबे, श्रीमती शिवानी नेगी, नवीन कुमार लोहानी, नवीन कुमार, अविनाश तिवारी, रविन्द्र सिंह, कैलाश सिंह, दीपेन्द्र कुमार, कमलेश सकलानी, श्रीमती रजनी पालीवाल, मुकेश कुमार, श्रीमती निशा बलूनी, कृष्णानंद उनियाल, प्रदीप रावत, ऋषिकपूर, श्रीमती अंजू देवी, सतेन्द्र सिंह रावत, कुलदीप, अर्जुन, सूरज सिंह एवं नगर निगम, ऋषिकेश के सफाई निरीक्षक अभिषेक मल्होत्रा विभा नामदेव आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री धामी ने दिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और आयुष को बढ़ावा देने के निर्देश

इंडिया वार्ता ब्यूरो

देहरादून । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को उत्तराखंड की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने और अस्पतालों में आवश्यक संसाधनों को सुदृढ़ करने के लिए विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि अस्पताल केवल रेफरल सेंटर बनकर न रह जाएं, बल्कि जन स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी ओनरशिप के साथ कार्य करे।

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि वे स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की अलग से बैठक करें। साथ ही, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मुख्यमंत्री घोषणाओं की अद्यतन स्थिति से भी अवगत कराने को कहा। बैठक में बताया गया कि राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए टेलीमेडिसिन के माध्यम से सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को मेडिकल कॉलेजों से जोड़ने की व्यवस्था की जा रही है।

आयुष विभाग को भी मिली नई दिशा

आयुष विभाग की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में दो स्पिरिचुअल जोन बनाने की घोषणा के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योग, वेलनेस और आयुष हमारी विरासत हैं, और राज्य में हेल्थ व वेलनेस के अच्छे केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से कार्य किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने वेलनेस सेंटर और वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक साल का लक्ष्य निर्धारित कर कार्य करने का आह्वान किया। पुराने हेल्थ और वेलनेस सेंटरों के उन्नयन पर भी जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त, जीएमवीएन, केएमवीएन और वाइब्रेंट विलेज में भी हेल्थ और वेलनेस सेंटरों की संभावनाओं पर कार्य करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य की योग नीति के तहत योग निदेशालय की स्थापना की जाएगी और योग केंद्रों का पंजीकरण किया जाएगा। नए योग केंद्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रदेश में निवेशक सम्मेलन के बाद आयुष के क्षेत्र में 1100 करोड़ रुपये की ग्राउंडिंग शुरू हो चुकी है। यह भी बताया गया कि प्रदेश के 300 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को एन.ए.बी.एच. (नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स) मानकों के अनुरूप उच्चीकृत किया जा रहा है, जिनमें से 149 का प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण हो चुका है।

प्रथम पृष्ठ का शेष युवाओं को कौशल विकास और रोजगार .

स्थापना की जाए तथा प्रदेश के दूरदराज इलाकों में स्किल ऑन व्हील्स वैन की शुरूआत की जाए। मुख्यमंत्री ने हेल्थकेयर और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में राज्य के युवाओं को विदेश में रोजगार से जोड़ने के लिए संबंधित देशों में स्थित भारत के दूतावासों से संपर्क किये जाने पर बल देते हुये ऐसे युवाओं को विदेशी भाषाओं के कोर्स कराने हेतु दून विश्वविद्यालय से नियमित समन्वय स्थापित किये जाने के भी निर्देश दिए। जनपदों में बनाए जा रहे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित किये जाने की भी बात मुख्यमंत्री ने कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक वर्ष कितने युवाओं को कौशल विकास और रोजगार से जोड़ा गया इसके विवरण के साथ दीर्घकालिक योजना के बारे में कौशल विकास विभाग 10 दिनों के भीतर स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत करे।

बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश के 27 आईटीआई में प्रशिक्षण ले रहे अभ्यर्थियों को दो वर्षीय कोर्स के अंतर्गत एक वर्ष का प्रशिक्षण आईटीआई में तथा एक वर्ष का प्रशिक्षण उद्योगों में प्रदान करने हेतु भारत सरकार से सहमति प्राप्त हो गई है। पाँच अन्य आईटीआई के लिए शीघ्र ही सहमति प्राप्त किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।

बैठक में उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद श्री विश्वास डाबर, मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, सचिव श्री श्रीधर बाबू अदांकी, श्री सी. रविशंकर एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

प्रथम पृष्ठ का शेष सीएम पुष्कर सिंह धामी का सख्त रुख...

कर्मी-नैनीताल जिले के रामनगर में विजिलेंस की टीम ने एलआईयू के उप निरीक्षक और मुख्य आरक्षी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। 04-रोडवेज एजीएम-काशीपुर में रोडवेज सहायक महाप्रबंधक को अनुबंधित बस संचालन के बदले 90 हजार रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया।

05-खंड शिक्षा अधिकारी-हरिद्वार के खानपुर ब्लॉक में खंड शिक्षा अधिकारी को ध्10 हजार की घूस लेते गिरफ्तार किया गया। 06-जीएसटी सहायक आयुक्त-देहरादून में कार्यरत जीएसटी सहायक आयुक्त को 75 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। 07-जिला आबकारी अधिकारी-रुद्रपुर में तैनात जिला आबकारी अधिकारी को शराब कारोबारी से 10 लाख रुपए के माल के एवज में 10 फीसदी रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हम देवभूमि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करते हुए, सुशासन की कार्य संस्कृति विकसित करना चाहते हैं। इसी क्रम में मुख्य सेवक के रूप में कार्यभार संभालने के दिन से ही विजिलेंस को भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान छेड़ने के निर्देश दिए, जिसका असर अब नजर आ रहा है। भ्रष्टाचारियों को अंतिम अदालत सजा दिलाए जाने के लिए भी मजबूत पैरवी की जा रही है।

दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता से मिला ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज पेपर्स फेडरेशन का प्रतिनिधिमंडल

देहरादून,इंडिया वार्ता ब्यूरो । । ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज पेपर्स फेडरेशन का एक 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरिंदर सिंह की अगुवाई में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का पत्रकारों व दिल्ली की जनता के लिए किए जा रहे विकास कार्यों के लिए आभार प्रकट किया। इस अवसर पर दिल्ली के पत्रकारों का एक मांग पत्र मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को सौंपा गया। अध्यक्ष ने फैडरेशन का सितंबर में होने वाले महाअधिवेशन का निमंत्रण भी दिया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री गुप्ता का राजस्थानी पगड़ी और भगवान श्रीराम की प्रतिमा भेंट सम्मान किया। राजस्थान ईकाई के अध्यक्ष प्रेस काउंसिल के सदस्य रहे डॉ- एलसी भारतीय ने मुख्यमंत्री को राजस्थानी पगड़ी पहनाई तथा भगवान श्रीराम की प्रतिमा भेंट की। राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरिंदर सिंह ने शॉल ओढ़ाई। डॉ. भारतीय मुख्यमंत्री को भारत की सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री बताया। प्रतिनिधिमंडल में उत्तराखंड के स्मॉल मीडियम बिग न्यूज पेपर्स सोसाईटी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार छाबड़ा, महासचिव राशिद अली, संगठन मंत्री हिमांशु छाबड़ा, यूपी के पवन सहयोगी, फेडरेशन के संगठन सचिव विजय सूद सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर दिल्ली के कस्तुरबा नगर से विधायक नीरज बेसौया भी थे। बसोया भारतीय जनता पार्टी के एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। ये 2008 और 2025 में दिल्ली के कस्तूरबा नगर से विधानसभा सदस्य चुने गए।

एजेस फ़ेडरल लाइफ़ इंश्योरेंस ने अपनी तरह का पहला इंडिया सेक्टर लीडर्स फंड लॉन्च किया

देहरादून,इंडिया वार्ता ब्यूरो । भारत में निजी क्षेत्र की प्रमुख जीवन बीमा कंपनियों में से एक, एजेस फ़ेडरल लाइफ़ इंश्योरेंस ने अपनी तरह के पहले इंडिया सेक्टर लीडर्स फंड के लॉन्च की घोषणा की है। ये फंड बिल्कुल अनोखा है, जो निवेशकों को मध्यम से लंबी अवधि के निवेश के साथ घरेलू इक्विटी में निवेश करने का अवसर देता है। इस लॉन्च के साथ, कंपनी अपने ग्राहकों को इस तरह का फंड उपलब्ध कराने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी बन गई है। यह फंड ?10 के फ्लैट नेट एसेट वैल्यू (NAV) पर लॉन्च किया जा रहा है, जो 14 जुलाई से शुरू हो रहे न्यू फंड ऑफर (ह्स्नह्र) के दौरान सीमित अवधि के लिए उपलब्ध रहेगा। इस फंड का उद्देश्य बीएसई इंडिया सेक्टर लीडर्स इंडेक्स के प्रमुख शेयरों में निवेश करके बेहतर रिटर्न देना है।

इस लॉन्च के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए,एजेस फ़ेडरल लाइफ़ इंश्योरेंस के चीफ़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर, श्री अतुल श्रीवास्तवने कहा, एजेस फ़ेडरल लाइफ़ इंश्योरेंस में, हम निवेश के ऐसे बेहतर विकल्प उपलब्ध कराने के इरादे पर अटल हैं, जो निवेशकों के निजी आर्थिक लक्ष्यों को लंबे समय में भारत की आर्थिक प्रगति के साथ जोड़ते हैं। इंडिया सेक्टर लीडर्स फंड सिर्फ़ एक फंड से कहीं बढ़कर है— यह निवेशकों को अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर और पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने का अवसर देता है। हम आज के निवेशकों को भारत के विकास की कहानी में अहम योगदान देने के अवसर प्रदान कर रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि हम इनोवेशन के साथ-साथ ग्राहकों को सबसे ज्यादा अहमियत देने और मजबूत वित्तीय समाधानों की पेशकश करने के अपने संकल्प पर कायम हैं। यह फंड इंडिया इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर में बताए गए 22 अलग-अलग क्षेत्रों में निवेश करता है, तथा एक विस्तृत एवं विविधतापूर्ण क्षेत्रों को शामिल करने वाला पोर्टफोलियो प्रदान करता है, जो किसी एक ही क्षेत्र में निवेश के जोखिम को कम करता है और पूरे बाजार में अवसरों का लाभ उठाता है। इस पेशकश के ज़रिए, एजेस फ़ेडरल लाइफ़ इंश्योरेंस निवेशकों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए इनोवेटिव वित्तीय समाधानों के माध्यम से अपने मिशन को आगे बढ़ा रहा है, ताकि निवेशक बड़ी आसानी से अपनी जमा-पूंजी को बढ़ा सकें। अधिक जानकारी के लिए, एजेस फ़ेडरल लाइफ़ इंश्योरेंस की अपनी नज़दीकी शाखा पर जाएँ या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक संदीप शर्मा ने इंडिया प्रिन्टर शांप न. 06 संगम प्लाजा धर्मपुर देहरादून से मुद्रित करवाकर मोहक्कमपुर खुर्द पोस्ट आई.आई.पी. रेलवे क्रसिंग हरिद्वार रोड़ देहरादून (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित किया।

प्रधान सम्पादक : संजीव शर्मा

संपादकः संदीप शर्मा

सह सम्पादक : डा. विष्णु बिश्वास

संजीव अग्निहोत्री गढ़वाल प्रभारी

अल्मोड़ा जिला प्रभारी : रोहित कार्की

अल्मोड़ा संवाददाता : रक्षित कार्की

ब्यूरो चीफ : राजीव अग्रवाल

Email.
indiawarta@gmail.com
indiawarta@rediffmail.com
Web Site
www.indiawarta.com
R.N.I NO. UTTHIN/2011/39104
M- 7500471414,7500581414

नोट& समाचार पत्र में सभी पद अवैतानिक हैं। किसी भी वाद विवाद का न्याय क्षेत्र देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा।

R.N.I NO. UTTHIN/2011/39104

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड़ के मदरसों में स्कॉलरशिप वितरण में हुयी धांधली पर दिए जांच के आदेश

सरस्वती शिशु मंदिर के नाम से अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति लेने के बाद मचा हड़कंप

इंडिया वार्ता ब्यूरो

देहरादून । सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल को कागजों में अल्पसंख्यक विद्यालय या मदरसा दर्शाकर केंद्रीय सरकार द्वारा पोषित विद्यालयों को दी जाने वाली छात्रवृति दिये जाने के प्रकरण की जानकारी होन पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गहनता से जांच करने के आदेश विशेष सचिव अल्प संख्यक कल्याण विभाग को दिए हैं। अब इस मामले की जांच विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण डॉ. पराग मधुकर धकाते द्वारा की जा रही है।

जानकारी के अनुसार उधम सिंह नगर जिले में 2021-2022 और 2022-2023 के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर दर्ज किए अल्पसंख्यक छात्रवृति आवेदकों की प्रमाणिकता जांचने के लिए उधमसिंह नगर जिले के 796 बच्चों के दस्तावेजों की जानकारी मांगी गई थी। इनमें से 6 मदरसों/शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले 456 बच्चों के बारे में जानकारी संदिग्ध पाई गई है। खास बात ये है कि इन स्कूलों में सरस्वती शिशु मंदिर हाईस्कूल किच्छा का नाम भी शामिल है।

यहीं से इस मामले में धांधली होने का मामला सामने आया है क्योंकि एक तो सरस्वती शिशु मंदिर अल्पसंख्यक विद्यालय नहीं होता दूसरा इसका संचालक मोहम्मद शारिक-अतीक बताया गया है। राष्ट्रीय छात्रवृति पोर्टल के अनुसार यहां 154 मुस्लिम बच्चों का पढ़ना बताया गया है। राष्ट्रीय छात्रवृति पोर्टल पर ये नाम देखकर सरकार भी चौंकी है जिसके बाद ही मुख्यमंत्री धामी ने गहनता से जांच करने के निर्देश दिए है। जानकारी के अनुसार काशीपुर के नेशनल अकादमी जेएमवाईआईएच एस में पढ़ने वाले 125 मुस्लिम छात्रों और इसके संचालक गुलशफा अंसारी, मदरसा अल जामिया उल मदरिया के 27 बच्चों का और उसके संचालक मोहम्मद फैजान का सत्यापन भी किए जाने के निर्देश जारी किए गए है। इसके अलावा मदरसा अल्बिया रफीक उल उलूम घनसारा बाजपुर के संचालक जावेद अहमद और यहां के 39 बच्चों, संभवत: इसी जावेद अहमद के नाम से गदरपुर के मदरसा जामिया आलिया के 24 बच्चों के बारे में भी दस्तावेज जांचने और मदरसा जामिया रजा उल उलूम बाजपुर के 85 बच्चों और संचालक इरशाद अली के सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं।

उधम सिंह नगर के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी नंदिनी सिंह को इन सभी मामलों की गहनता से जांच पड़ताल करने के लिए सचिव अल्पसंख्यक कल्याण ने निर्देश दिए हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर राष्ट्रीय छात्रवृति पोर्टल में दर्ज उत्तराखंड राज्य के ऐसे सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के बारे में आवेदकों के सत्यापन, भुगतान के विषय में बैंक खातों की जानकारी, संचालकों और विद्यार्थियों दोनों के जांचने के निर्देश देते हुए दो हफ्तों में रिपोर्ट देने को कहा है।

इस संबंध में विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण डॉ. पराग मधुकर धकाते ने बताया कि सरस्वती शिशु मंदिर के नाम से एक वर्ग विशेष द्वारा अल्पसंख्यक छात्रवृति के मामले संज्ञान में आने साथ ही अन्य मदरसों के द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृति में दर्ज आवेदनों को लेकर संदेह पैदा हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इस मामले की गहनता से जांच करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस पर पूरे राज्य में जांच की जा रही है साथ ही केंद्र सरकार के मंत्रालय से भी संवाद किया जा रहा है।

राज्य में राष्ट्रीय छात्रवृति पोर्टल में दी गई आवेदकों की जानकारी संदेहजनक प्रतीत हुई है, जिसमें सरस्वती शिशु मंदिर के नाम से छात्रवृति का प्रकरण भी समाने आया है जिसकी जांच करने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव को निर्देशित किया गया है। देवभूमि में भ्रष्टाचार के मामलों को किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

फ्लेवर्स ऑफ होम शेफ्स और टेस्ट ऑफ होम बेकर्स पुस्तकों का विमोचन करते कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी

इंडिया वार्ता ब्यूरो

देहरादून । सुबे के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हाथीबड़कला स्थित कैंप कार्यालय में लेखिका दीपा चावला द्वारा रचित दो पुस्तकों फ्लेवर्स ऑफ होम शेफ्स एवं टेस्ट ऑफ होम बेकर्स का विमोचन किया। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने लेखिका दीपा चावला और सभी प्रतिभागी महिलाओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा, यह केवल पुस्तक विमोचन नहीं, बल्कि उन महिलाओं की वर्षों की मेहनत और निपुणता को पहचान देने का प्रयास है, जिन्होंने घर की चारदीवारी के भीतर रहकर पाक कला में दक्षता हासिल की है। अब इन प्रतिभाओं को मंच और पहचान मिल रही है, जो अत्यंत सराहनीय है। कृषि मंत्री जोशी ने कहा कि आज महिलाएं समाज के हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं और प्रदेश सरकार महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 करोड़ लखपति दीदी के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में उत्तराखंड सरकार ने अब तक 1.65 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाया है। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से मातृ शक्ति को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है और राज्य सरकार इस दिशा में सतत प्रयासरत है। मंत्री जोशी ने महिलाओं की प्रतिभा को प्रोत्साहन देने के लिए इस तरह के प्रयासों को अत्यंत प्रेरणादायक बताया।

इस मौके पर लेखिका दीपा चावला के साथ-साथ प्रिया गुलाटी, पूजा रावत, रोमी सलूजा, अंजना साहनी, शिवानी कौशिक गुप्ता, आदर्श भाटिया, मधु चावला, नीता कंसारा, लता कपूर, अर्चना गोयल, अंजना वही, तृप्ति जुयाल सेमवाल और पारुल अग्रवाल जैसी कई प्रतिभाशाली महिलाएं भीउपस्थितरहीं।

पाठको के लिए

मान्यवर पाठकगण

१. दैनिक इंडिया वार्ता समाचार पत्र हेतु अपने व्यक्तिगत या संस्थान की ओर से प्रकाशनार्थ लेख/समस्याएं व समाचार हमें भेजे व प्रति दिन नियमित रूप से समाचार पत्र प्राप्त करने को कार्यालय से सम्पर्क करे।

२. समाचार पत्र के बारे में आप के विचार व सुझाव आमंत्रित है।

३. नियमित पाठक बनने के लिए आपके द्वारा समाचार पत्र की सदस्यता ग्रहण करना प्रार्थनीय है।

४. व्यक्तिगत एवं व्यापारिक संस्थानो के तथा अन्य विज्ञापन आमंत्रित है।

सम्पादक

दैनिक इंडिया वार्ता

कार्यालय : मोहकमपुर खुर्द नियर आई आई पी हरिद्वार रोड देहरादून।

दूरभाष: 7500581414,9359555222

धूमधाम से मनाया जाएगा, कारगिल विजय शौर्य दिवस

देहरादून, गांधी पार्क में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम, मा0 मुख्यमंत्री करेंगे प्रतिभाग,

देहरादून,इंडिया वार्ता ब्यूरो । कारगिल विजय दिवस, शौर्य दिवस के रूप में धूमधाम और उत्साह से मनाया जाएगा। शौर्य दिवस के अवसर पर 26 जुलाई को गांधी पार्क, देहरादून में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों के क्रम में कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बृहस्पतिवार को अपर जिलाधिकारी (एफआर) केके मिश्रा ने सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्यक्रम की सभी तैयारियों को समय पर पूर्ण किया जाए।

अपर जिलाधिकारी ने कहा कि शौर्य दिवस पर समस्त कार्यक्रम गांधी पार्क, देहरादून में आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर शहीद हुए जवानों के परिजनों, वीरांगनाओं और माताओं को मा0 मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे। उन्होंने सैनिक कल्याण एवं परिवहन अधिकारी को कारगिल शहीद परिवार के आश्रितों, पूर्व सैनिकों को कार्यक्रम स्थल पर लाने ले जाने हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए। नगर निगम को कार्यक्रम स्थल एवं आस पास सड़क एवं प्रमुख मार्गो पर विशेष साफ सफाई, मोबाइल टॉयलेट एवं अन्य व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। एसपी ट्रैफिक को वाहनों की पार्किंग एवं यातायात को सुचारू बनाए रखने को कहा। सैनिक कल्याण विभाग को कार्यक्रम स्थल पर टैंट, वैरिकेडिंग, सीटिंग, स्टेज, सजावट, पेयजल की इत्यादि की व्यवस्था मानकों के अनुसार सुनिश्चित की जाए। साथ ही सैनिक कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए कि शौर्य दिवस पर दो राज्यसभा, दो लोकसभा एवं दस विधान सभा सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर नगर निगम देहरादून को विशेष रूप से कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाए।

अपर जिलाधिकारी ने शौर्य दिवस से एक दिन पूर्व 25 जुलाई की सायं 5 बजे से प्रमुख चौराहों पर देश भक्ति गीतों का प्रसारण के साथ ही कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति तैयार करने हेतु संस्कृति विभाग को निर्देश दिए। शिक्षा विभाग को स्कूलों में जूनियर वर्ग में पेंटिंग एवं सीनियर वर्ग में निबंध प्रतियोगिता आयोजित कराते हुए विजेताओं की सूची कार्यक्रम स्थल पर उपलब्ध कराने को कहा ताकि विजेता छात्रों को कार्यक्रम के दौरान पुरस्कृत किया जा सके।

बैठक में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल (से.नि) ओम प्रकाश फस्वार्ण, सहायक जिला सैनिक कल्याण अधिकारी एसके साहिनी, सीईओ वीके ढ़ौडियाल, सीओ सिटी विवेक सिंह कुटियाल, एसआई नगर निगम राजेश बहुगुणा, फायर ऑफिसर किशोर उपाध्याय सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।